भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2757

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

आध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधार

2757 **श्री भाष्यम् रामा कृष्णाः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रत्यायन सहायता**,** अनुसंधान प्रोत्साहन और बहु-विषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से आंध्र प्रदेश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं**;**

(ख) राज्य में उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या में कौशल विकास और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के एकीकरण में क्या प्रगति हुई है**;**

(ग) क्या छात्रों**,** विशेषकर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों और ग्रामीण शिक्षार्थियों को बहु-प्रवेश एवं निकास तथा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसे लचीले विकल्पों का सार्थक उपयोग करने में सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त करियर परामर्श और जागरूकता तंत्र मौजूद हैं**;** और

(घ) आंध्र प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने और वंचित वर्गों की पहुँच में समता सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की जा रही हैं**?**

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और नवाचार और बहु-विषयक शिक्षा पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की सुविधा प्रदान की है।

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की है जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अनुसंधान क्षमता का दोहन करने, अकादमिक अनुसंधान का समर्थन करने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुवाद अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है।

अनुसंधान विकास और नवाचार, प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना, शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना, इम्प्रिंट, और उच्चतर आविष्कार योजना जैसी अन्य पहल शिक्षा, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच अनुसंधान क्षमता, नवाचार और सहयोग का संवर्धन जारी रखती हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई, 2025 में आयोजित अपनी बैठक में 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आईआईटी तिरुपति सहित पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित शैक्षणिक और बुनियादी ढांचा क्षमता के विस्तार को अनुमोदन दिया है जिसमें से 2025-26 से 2028-29 की अवधि के लिए आईआईटी तिरुपति को 2313 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यूजीसी ने अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। जुलाई 2026 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 38 उच्चतर शिक्षण संस्थानों सहित देश भर में 1,722 उच्चतर शिक्षण संस्थानों ने इन दिशानिर्देशों के तहत अनुसंधान एवं विकास (अनुसंधान एवं विकास) प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान, विकास, कौशल विकास और नवाचार में उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए सतत और बेहतरीन विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज प्रणाली पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके अलावा एनईपी 2020 के अनुरूप यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिससे एचईआई को विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की प्रस्तुत करने और छात्रों को अधिक शैक्षणिक विकल्प और लोचशीलता प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है।

अनुसंधान संवर्धन, परस्पर संवाद, कौशल विकास और बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए, एनआईटी आंध्र प्रदेश ने कई पहल की हैं जैसे नवाचार और उद्यमिता का समर्थन करने के लिए एक इन्क्यूबेशन और स्टार्ट-अप केंद्र (ईआईएससी) की स्थापना, अकामिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) द्वारा समर्थित पाठ्यचर्या लचीलापन तथा व्यापक एकल विषय एवं स्वतंत्र संस्थानों को बहु-विषयक पारिस्थितिकी तंत्र और शैक्षणिक संसाधनों के साझाकरण हेतु क्षेत्रीय नेटवर्क में रूपांतरित करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) घटक के तहत श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति हेतु 100 करोड़ रुपये के अनुमोदन सहित कुल 33 इकाइयों को 378.74 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) तिरुपति की स्थापना मूलभूत विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विज्ञान में सबसे अग्रणी तथा अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए बेहतरीन अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। एनईपी 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार कई अंतःविषय पाठ्यक्रम आईआईएसईआर में शुरू किए गए हैं और छात्रों को प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख): यूजीसी ने सामुदायिक कॉलेजों, बी.वोक डिग्री कार्यक्रमों और दीन दयाल उपाध्याय केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत कौशल-आधारित शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आंध्र प्रदेश में 96 एचईआई को एनएसक्यूएफ के तहत कौशल-आधारित कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा यूजीसी ने उद्योग-प्रासंगिक कौशल के साथ अकादमिक शिक्षा को एकीकृत करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी), 2025 को प्रस्तुत करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए एनसीआरएफ, एनएचईक्यूएफ और पाठ्यक्रम तथा क्रेडिट फ्रेमवर्क शैक्षणिक, व्यावसायिक, कौशल-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण के लिए लोचशीलता प्रदान करते हैं। यूजीसी ने आंध्र प्रदेश में एईडीपी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 06.02.2026 को श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति में चौथे क्षेत्रीय एईडीपी सम्मेलन का भी आयोजन किया।

अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में 2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (i) आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नंबुरू, गुंटूर जिला, और (ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम परिसर, आंध्र प्रदेश ने अपने तीन वर्षीय स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों के भाग के रूप में एईडीपी पाठ्यक्रम लागू किए हैं।

(ग): एनईपी, 2020 के अनुरूप बहु-विषयक और लोचशील उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। यूजीसी ने एचईआई में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु-प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है, जो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के माध्यम से लोचशील अधिगम के रास्ते और अकादमिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने और नवाचार एवं अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार योजना भी कार्यान्वित कर रही है।

यूजीसी अपने नियामक दिशानिर्देशों, परामर्श और एचईआई के संवेदीकरण के माध्यम से इन प्रावधानों के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें एचईआई उपलब्ध शैक्षणिक मार्गों, क्रेडिट अंतरण, पुन: प्रवेश और कार्यक्रम विकल्पों के बारे में छात्रों को उन्मुख और परामर्श देने के लिए जिम्मेदार है। यह ग्रामीण और पहली पीढ़ी की पृष्ठभूमि के छात्रों

को अपने कार्यक्रमों की निरंतरता, गतिशीलता और उसे पूरा करने के बारे में अच्छा विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है।

दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार यूजीसी के दायरे में आंध्र प्रदेश में 298 एचईआई एबीसी पोर्टल पर पंजीकृत थे जिसमें 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 9 संवत विश्वविद्यालय, 12 निजी विश्वविद्यालय, 28 राज्य विश्वविद्यालय और 246 स्वायत्त कॉलेज शामिल थे।

एबीसी/एपीएएआर के माध्यम से डिजिटल अकादमिक रिकॉर्ड की उपलब्धता, स्वयम, ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लोचशील अधिगम के अवसरों के साथ, छात्रों की गतिशीलता और वैकल्पिक शिक्षण मार्गों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

(घ): सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और पहुंच की समता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा की पहुंच, लोचशीलता और पहुंच का विस्तार करने के लिए उपाय किए हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने संबंधी दिशानिर्देश छात्रों को अपनी पसंद के कार्यक्रम का चयन करने और अपने घर के निकट विविध विषयों तक पहुँच में सहायक होते हैं।

इसके अलावा स्वयम शिक्षार्थियों को किसी भी समय और कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करता है और यूजीसी के विनियम द्वारा एचईआई को स्वयम के माध्यम से एक सेमेस्टर में एक कार्यक्रम में 40 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति हैं। यूजीसी एमओओसी और ई-पीजी पाठशाला लगभग 23,000+ पीजी ई-सामग्री संसाधनों सहित गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करते हैं। सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, यूजीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से अपने ई-सामग्री और स्वयं पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया है और तेलुगु सहित आठ क्षेत्रीय भाषाओं में चयनित सामग्री उपलब्ध कराई है।

स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल व्याख्यान, ट्यूटोरियल और अध्ययन सामग्री सहित 24/7 चैनलों के माध्यम से निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री प्रदान करते हैं जिससे दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों में शिक्षार्थियों तक पहुंच का विस्तार होता है और डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलती है।

जनजातीय समुदायों के बीच समता को बढ़ावा देने और गुणवत्तापरक उच्चतर शिक्षा तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश के केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय सहित तीन केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के लिए सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2014-15 में 31.5 से बढ़कर 2023-24 में 35.5 हो गया है।

*****